THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): You may go.

[*At this stage, the hon. Member left the Chamber*]

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI (Gujarat): Sir...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): I have not allowed you. Nothing will go on record, whatever he says.

STATEMENT BY MINISTER—

Situation arising out of the Cyclonic storm in the Bay of Bengal and relief measures undertaken by the Central and State Governments of Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Union Territory of Pondicherry.

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नितिश कुमार): महोदय, मेरे साथी श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा आंध्र प्रदेश में आये समुद्री तूफान से उत्पन्न स्थिति के बारे में दिनांक 10.5.1990 को संसद को अवगत करा दिया था। अब कुछ और ब्यौरा उपलब्ध हो चुका है, अतः मैं सदन की अनुमति से अभी तक हुई क्षति और किए गए राहत उपायों के संबंध में अद्यतन स्थिति के बारे में एक वक्तव्य देना चाहता हूं।

जैसा कि माननीय सदस्यों को पता ही है कि तेज हवा के साथ-साथ भीषण समुद्री तूफान 9 मई, 1990 को कृष्णा नदी (मचलीपटनम् के दक्षिण में) के पास दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट को पार कर गया था। इसके साथ लगभग 200 से 240 कि० मी० घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चली तथा समुद्र में 5 से 6 मीटर की ऊंचाई की लहरें तट से टकराई। इसके फलस्वरूप उत्तरी तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र, उड़ीसा के तटीय क्षेत्र के कुछ स्थानों तथा पश्चिम बंगाल के एक या दो स्थानों एवं त्रिपुरा में भारी वर्षा से लेकर अधिक भारी वर्षा रिकार्ड की गई।

आंध्र प्रदेश के सभी तटीय जिलों में इस समुद्री तूफान से सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। कृष्णा और गुंटुर जिले बुरी तरह से इसकी चपेट में आये। इसके अतिरिक्त अन्य प्रभावित जिले पश्चिम गोदावरी, पूर्वी गोदावरी, प्रकासम्, विशाखापटनम, विजियानगरम श्री काकुलम और नेल्लौर है। कम प्रभावित अन्य जिले खम्माम, महबूबनगर वारंगल, नालगौडा और चित्तूर हैं। इन जिलों के कुछ भाग बाढ़ और भीषण वर्षा के कारण जलमग्न हो गये थे। समुद्री तूफान का प्रभाव तमिलनाडु राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश पांडिचेरी में भी कुछ जगहों पर महसूस किया गया, हालांकि यह प्रभाव गंभीर रूप से नहीं पड़ा।

आंध्र प्रदेश सरकार से 22 मई, 1990 की स्थिति के अनुसार जन-जीवन और सम्पत्ति को हुई क्षति के संबंध में प्राप्त ताजा रिपोर्ट के अनुसार स्थिति इस प्रकार है :—

1.	प्रभावित जिले	14
2.	प्रभावित जनसंख्या	107.07 लाख
3.	प्रभावित गांव	5.717
4.	जनजीवन की हानि	976
5.	पशुओं की हानि	22,184
6.	भेड़/बकरियों की मृत्यु	42,950
7.	कुक्कुटों की मृत्यु	36.98 लाख
8.	बत्तखों की मृत्यु	6,274
9.	क्षतिग्रस्त मकान	9.19 लाख 4.79 लाख आंशिक रूप से तथा 4.40 लाख पूरी तरह से)
10.	व्यक्तियों को संख्या जिनसे स्थान खाली करवाया गया	6.57 लाख
11.	आयोजित राहत कैम्प	1535
12.	कृषि तथा अन्य सार्वजनिक सेवाओं को पहुंची क्षति	792.78 करोड़ रुपये

हानि और क्षति के बारे में निश्चित ब्यौरों का निर्धारण आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है और पूरी और सही स्थिति का पता लगने में अभी और समय लगेगा। तथापि, उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि कृषि और बागबानी फसलों, कुक्कुट, दूर संचार, सड़कों तथा पुलों, रेल पटरियों, संबंधी संबंधी व्यवस्था मकानों और पेयजल पद्धति को व्यापक हानि और क्षति पहुंची है। इसी प्रकार तमिलनाडु और केन्द्र शासित प्रदेश पांडिचेरी की सरकार से क्षति के ब्यौरे की प्रतीक्षा की जा रही है। तथापि, तमिलनाडु और पांडिचेरी के मामले में जनजीवन की हानि क्रमशः 7 और 2 रही है। अभी जो रिपोर्ट मिली है उसमें 13 है।

तूफान के संबंध में भारत के मौसम विज्ञान विभाग से चेतावनी प्राप्त होने पर, आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने निचले इलाकों से लोगों को निकालने में समय से कार्रवाई की। विस्थापित लोगों को राहत शिविरों में रखा गया जहां उनके भोजन की भी व्यवस्था की गई। इसी प्रकार, तमिलनाडु और पांडिचेरी की सरकार ने भी स्थिति से निबटने के लिए निवारक उपाये किये। सदस्यों को याद होगा कि आंध्र प्रदेश में 1977 के तूफान में मरने वालों की संख्या 10,000 थी। फिर भी, समय पर निवारक उपाय कर लिये जाने के कारण इस बार जन-जीवन की हानि बहुत ही कम रही। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने स्थिति की बहुत गहराई से मोनिटरिंग की और इस तूफान के आने के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को सूचित रखा। लोगों को चेतावनी देने के लिए नियमित रूप से बुलेटिन जारी किए गए। उनके प्रयास प्रशंसनीय हैं।

हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने स्थिति का व्यक्तिगत रूप से जायजा लेने के लिए आंध्र प्रदेश के तूफान पीड़ित क्षेत्रों का दो बार अर्थात् 12 और 19 मई को दौरा किया। उन्होंने दूसरे अनेक उपायों के साथ-साथ प्रधान मंत्री सहायता कोष से 2.00 करोड़ रुपये मंजूर किये। उन्होंने राज्य की आपदा राहत निधि के केन्द्रीय हिस्से की आधी राशि, जो 32.50 करोड़ रुपये है, की अदायगी की घोषणा भी की जो 14 मई, 1990 को राज्य सरकार को निर्मुक्त कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा पहले निर्मुक्त की गई राशि व्यय कर लिये जाने पर 32.50 करोड़ रुपये की शेष राशि भी तत्काल निर्मुक्त कर दी जायेगी।

उप प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री ने मृत व्यक्तियों के परिवारों को वितरण किये जाने हेतु इंडियन पीपुल्स नेचुरल केलेमिटीज़ ट्रस्ट से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों और संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी को वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस संबंध में, माननीय सदस्यों को मेरे साथी श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा द्वारा इस सदन में 11 मई, 1990 को दिया गया वक्तव्य याद होगा जिसमें यह कहा गया था कि इंडियन पीपुल्स नेचुरल केलेमिटी ट्रस्ट से प्रत्येक मृत व्यक्ति के परिवार को 25,000/–रुपये प्रदान किए जायेंगे। चूंकि इस घोषणा के बाद प्रधान मंत्री सहायता कोष से 2 करोड़ रुपये मंजूर किए गए, जिसमें प्रत्येक मृतक व्यक्ति के निकटतम संबंधी को 10,000/–रु० दिया जाना शामिल है, अब यह निर्णय किया गया है कि इंडियन पीपुल्स नेचुरल केलेमिटी ट्रस्ट से आंध्र प्रदेश के लिए प्रति मृतक की सहायता राशि को 15,000/–रु० तक सीमित कर दिया जाये जिससे उस प्रदेश में प्रत्येक मृत्यु के मामले में वित्तीय सहायता को कुल राशि 25,000 रुपये हो जाये।

प्रधान मंत्री जी द्वारा आंध्र प्रदेश के किए गए दो दौरों के उपरान्त प्राप्त कई निर्देशों के अनुसरण में राज्य सरकार की अत्यन्त जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने और समुद्री तूफान से उजड़े लोगों को सभी संभव सहायता देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत किए गए आवटनों के अलावा, आंध्र प्रदेश सरकार को चावल की 50,000 मीटरी टन अतिरिक्त मात्रा दी गई है। 15,000 मीटरी टन फास्फेट युक्त उर्वरक और 500 मीटरी टन खाद्य तेल का अतिरिक्त

[श्री नितीश कुमार]

आवंटन भी उन्हें किया गया है । आंध्र प्रदेश सरकार को उनकी मांग के अनुसार हैजा के टीके की 10 लाख खुराक और 50 मीटरी टन ब्लीचिंग पाउडर भी उपलब्ध कराया गया है । पैट्रोलियम उत्पाद अर्थात् पैट्रोल, डीजल, एल.पी.जी. और मिट्टी के तेल की पर्याप्त मात्रा राज्य को उपलब्ध कराई गई है ।

वर्षा के पानी से भीगे या मलिन हो गये धान तथा चावल की खरीद के मानदंडों में ढील दी गई है और भारतीय खाद्य निगम को निर्देश दिए गए हैं कि व मानव उपभोग के लिए उपयुक्त धान और चावल की खरीद करें । सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों/बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रभावित लोगों को आवश्यक राहत प्रदान करने के लिए क्षेत्रों/गांवों–कस्बों को अपनायें । ऋणों की वसूली को स्थगित करने और उनका पुनः निर्धारण करने के बारे में भी बैंक कार्रवाई कर रहे हैं । आंध्र प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा नए उपभोग ऋण दिए जा रहे हैं । राष्ट्रीय बीज निगम को निर्देश दिए गए हैं कि वह आंध्र प्रदेश राज्य को गुणवत्ता प्राप्त बीजों की पर्याप्त मात्रा भेजकर उनकी मांग को पूरा करें । कृषि बागबानी फसलों के पुनः लगाए जाने के लिए आकस्मिक योजनायें तैयार की जा रही हैं । सभी सबधित बीमा एजेंसियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे बीमा दावों का शीघ्र निपटान करें । विभिन्न आवास विकास एवं वित्तीय व्यवस्था करने वाली एजेंसियों से अनुरोध किया गया है कि वे चक्रवात से ह गए मकानों के स्थान पर पक्के मकान तैयार करने के लिए उदार शर्तों पर ऋण सु विधायें प्रदान करें ।

कृषि एवं सहकारिता विभाग में गठित क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप शुरू से ही राहत एवं पुनर्स्थापन सम्बन्धी स्थिति की मानीटरिंग कर रहा है । आवश्यक सेवाओं को प्रदान करने वाले केन्द्र सरकार के सभी विभाग इस ग्रुप के सदस्य हैं । ये सभी विभाग पुनर्स्थापन कार्यों को युद्ध-स्तर पर चला रहे हैं जिससे कि जहां तक संभव हो कम से कम समय में सभी आवश्यक सेवाओं को सामान्य स्थिति में लाया जा सके । प्रधान मंत्री जी के निर्देश पर दूर संचार सड़क परिवहन, बिजली तथा रेलवे से संबंधित क्षति का अनुमान लगाने और मरम्मत/पुनर्स्थापन कार्य करने के लिये विभिन्न केन्द्रीय विभागों द्वारा कार्यकारी दलों का गठन किया गया है । आन्ध्र प्रदेश के बिजली का उत्पादन करने वाले केन्द्रों को कोयले की सप्लाई में सुधार लाने के लिए वैस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड से कोयले की सप्लाई को अधिकतम किया जा रहा है । सिंगरेनी कोल फील्ड से कोयले के उत्पादन और सप्लाई में भी सुधार किया गया है ।

सशस्त्र सेना अर्थात् थल सेना, नौ सेना और वायु सेना द्वारा मुहैया की गई सहायता का विशेष उल्लेख किए जाने की जरूरत है । मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर भी राज्य सरकार को सभी सहायता मुहैया की । अलग-थलग पड़ गए क्षेत्रों से लोगों को निकाला गया और उन क्षेत्रों में खाद्य सामग्री, पेयजल आदि विमान से गिराया गया जहां अन्य किसी भी साधन से नहीं पहुंचा जा सकता था ।

आठ सदस्यों वाला एक केन्द्रीय दल 13 से 16 मई, 1990 के बीच आन्ध्र प्रदेश राज्य को भेजा गया था ताकि स्थिति का सामना करने के लिये अपेक्षित राहत उपायों का मौके पर जायजा लिया जा सके और राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित तत्काल सहायता का आकलन किया जा सके । इस दल द्वारा सुझाये गये विभिन्न उपायों को क्रियान्वित करने के लिये पहले ही कार्यवाही शुरू की जा चुकी है ताकि प्रभावित लोगों को आवश्यक राहत प्रदान करने में राज्य सरकार की सहायता की जा सके ।

सदन को मैं एक बार फिर से यह आश्वासन देना चाहूंगा कि समुद्री तूफान से उत्पन्न स्थिति का कारगर तरीके से सामना करने में आन्ध्र प्रदेश की जनता और सरकार को आवश्यक सहायता प्रदान करने में कोई भी कसर नहीं रखी जायेगी ।

THE THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): Before I call the hon. Members for seeking clarifications, I would like to say that there are 12 hon. Members who would like to seek clarifications. The first thing is that no more names will be added to this list and no hon. Member will get more than 2 minutes to seek clarifications. They should straightway seek clarifications from the Minister. Only two minutes are given for each Member because we have to discuss the price rise situation, we have to discuss the steel subject and other things also. Since today is the last day of the session, we want to cover everything. Please cooperate with the Chair.

DR. NARREDDY THULASI REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I take this opportunity to appreciate the National Front Government at the Centre for providing immediate possible assistance to the Congress-I ruled State Government.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): I am giving you only two minutes. Please don't appreciate or downgrade anybody. Please ask questions.

DR. NARREDDY THULASI REDDY: Regarding evacuation of the people from Low-lying areas, that was okay but the post-cycle operations, relief and rehabilitation operations are hopeless in the State of Andhra Pradesh. In Guntur district, Baptla mandal, Appapuram village, police firing has taken place on the cyclone-affected people and two persons, namely, Chinthala Subba Rao and Chinthala Venkateswarulu died. Nowwhere in India or now where in the world this type of incident has taken place. Two Ministers of the Andhra Pradesh Government went to the sage of submiting their resignations because of misapropriation of the funds in the State. The Chief Minister of Andhra Pradesh has gone to America. *Rasta-roko, dharna,* gheraos and the policefiring are taking place in the cyclone-affected coastal areas. There is a political cyclone but not the natural cyclone in Andhra Pradesh. I would like to bring this to the notice of the Central Government.

The second point is that Dr. K.L. Rao, the famous engineer in his report said that sarugudu trees with a breadth of 3 KMs. along the coastal line of Andhra Pradesh should be grown. I request the Central Government to take up this work with the help of the State Government.

The next point is that according to one assessment there is need of 1,336 cyclone shelters along the coast. Now, there are only 788 cyclone shelters. Still there is need for 548 cyclone centres. The State Government of Andhra Pradesh has sent a report to the Central Government regarding the construction of a coastal road from Tada to Ichhapuram. I would request the Cenral Government to take this decision also. Thank you.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI (Andhra Pradesh) : Sir, there is a complete breakdown of the State Government machinery in Andhra Pradesh and a civil war is going on among the Ministers on the one hand and the officials on the other.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): You ask clarifications because you have only two minutes. That is why I am suggesting this.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: In Guntur district and several other places, the officials are kept captive and the people are

[Dr. Yelamanchili Sivaji]

being gheraoed, riots and bandhs are going on and a firing took place against the cyclone victims and there is a very tragic scene in Andhra Pradesh. As mentioned earlier, the Chief Minister fled away to U.S.A. I would like to know what steps are being taken...

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): Sir, he has gone there for medical treatment. (*Interruption*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): Don't reply to him.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: According to the Ninth Finance Commission, sufficient harm has been done to coastal areas where the cyclone has become a regular feature and we are having more than ten or fifteen cyclones every year. (*Interruptions*). Three-fourths of the damage has been done to the farming community but not even ten paisa went to the farming community for relief or rehabilitation. I would like to know what steps the Government has taken to see that the relief and rehabilitation measures percolate to the farming community. (*Time-bell rings*). So, no help to the farmers. I would like to know from the Minister how the Union Government is monitoring the utilisation of the funds that are being sent from the Centre to the State Government is in this regard.

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे (गुजरात): वाइस चेयरमैन, साहब, जब पहली बार कृषि मंत्री जी, वर्मा जी ने यहां पर स्टेटमेंट दिया था 11 मई को I had categorically asked the Minister whether there is any effect of the cyclone in Gujarat State in Panchmal district. At that time, the Minister was not having the necessary information and he informed the House that he is trying to have the information and will report to the House afterwards.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): This is a statement not on Gujarat. Kindly ask clarifications only about this statement.

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : मैं पूछ रहा हूं कि आज दिन तक, इस स्टेटमेंट के बाद भी पंचमहल जिले में 6 लोग मर गये हैं, कई घरों को नुकसान हुआ है और खेती की जमीन का भी नुकसान हुआ है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : उसका इस स्टेटमेंट से कोई संबंध नहीं है ।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : उस दिन मैंने कहा था कि Sir, this is the third statement made by the Agriculture Minister. इसलिए मैं पूछ रहा हूं...(समय की घंटी) कि क्या इसमें गुजरात जिले के पंचमहल डिस्ट्रिक्ट का समावेश है तथा जो सहायता आंध्र प्रदेश के लोगों को दी गई है, उसी तरह की सहायता पंचमहल डिस्ट्रिक्ट के लोगों को भी दी जायेगी या नहीं । अगर सहायता दी गई है तो आज दिन तक कितनी दी गई है ?

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Sir, I think, two minutes will not suffice. I am on pointed questions. This statement is dated 22nd. The Minister has given information up to 22nd and he says that pieces of information are flowing in What is the position as on Ist June? I want to know. Is there any addition to the deaths? Is there any addition to the losses? What information have you got regarding Andhra? Similarly, What is your information about Tamil Nadu and Pondicherry? You have said that you are awaiting reports. And how many have been kept in relief camps? What is their total number? How many camps have you organised? How many families are kept there and what is the total number under relief camps?

When the Ministry makes a statement on the floor of the House, that gets the approval of the House and

the Ministry has no authority to change it. That is why while seeking clarifications on the last statement, I pointedly said, "Don't use the Parliamentary forum to announce your trust funds." I also said, "Today it is only 80. Tomorrow it may increase. Are you going to give assistance, still at the rate of Rs. 25,000/- per death?" (*Interruptions*). When I asked that on that day, the entire Andhra battalion rose up and said, "Why are you coming in the way of their getting assistance". Today I am asking, why Andhra is keeping quiet when the assistance is reduced? The Deputy Prime Minister announced Rs. 25,000/- per death. Today, the Agriculture Ministry headed by the Deputy Prime Minister has withdrawn Rs. 10,000/-per death. I am questioning this. It is a question of propriety of this House. He has made an announcement in the House that he would be paying Rs. 25,000/- out of that fund, per death. Today he has reduced it to Rs. 15,000/- and added Rs. 10,000/- from the Prime Minister's Fund. That two crores of rupees was in addition. The Deputy Prime Minister made a statement on the floor of the House. He cannot go back on his statement. He should continue to pay Rs. 25,000/-per death out of that fund

You have said that you have supplied cholera vaccine and bleaching powder. Is there any report of any disease? How many have suffered and how many have been treated? Have you got any figures? You have said that paddy which is consumable can be purchased by the Food Corporation of India. Have you assessed the loss and what are you going to do about the loss of crops that the farmers have suffered? The paddy which was harvested and kept in the land has been washed away. Have you assessed the loss? Are you going to compensate the loss suffered by the farmers?

THE VICE-CHAIRMAN: (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI) : Please conclude.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: I am on pointed questions. Please allow me.

This is my last question. You warned from the Chair that this should not be used for political advantage. But I cannot restrain myself from condemning this Statement because it is politically motivated. Why? Because you have a courtesy to praise.....(*Interruptions*).

THE VICE CHAIRMAN: (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI) : Thank you. Sitdown. Mr. Hanumantha Rao.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: You have a courtesy to support. (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): Yes. Mr. Hanumantha Rao. It your turn. You can speak. (*Interruptions*). Please sit down, Mr. Hanumanthappa.

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, this report is given. Of late, so many other things are happening. There is havoc created by indiscriminate use of relief funds. That is also there. I do not want to go into all those 6 p.m. details. But, at the smae time, the change in the attitude of the National Front Government is a welcome feature this time because no discrimination is shown by the National Front Government with regard to a State which is led by the Congress (I), the Opposition Party here. That is exactly why, as we demanded earlier, the Prime Minister went twice in a week to the cyclone-affected areas and immediately the required funds were allotted. But this was not done earlier. We had asked for a Central Team for studying the situation there which has also been sent immediately after the happening. These are all welcome features... (*Interruptions*) We all welcome the change in the attitude of the National Front Government. But, at the same time, I would say that that is not enough. the havoc is enormous and the Central

[Shri Moturu Hanumanthapa Rao]

team would have studied the situation. But this amount of Rs. 64 crores is not enough. Considering the damage as assessed by the State Government, it comes to about Rs. 800 crores. So, more money should be allotted for relief work.

There are two or three more points on which I would like to seek clarifications.

Rescheduling of loans have been suggested here but that is not enough because the paddy-growing farmers and the horticultural-crop-growing farmers have lost everything therefore, the loans of these people who have lost all the crops must be written off, not just rescheduled. Simple rescheduling of the loans would not benefit them at all since they have lost everything This is very important and this should be considered by the Government.

THE VICE-CHAIMAN (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI) : You have taken enough time. Please conclude.

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO : There is another thing. If the paddy is fit for human consumption, that can be purchased If it is not fit for human consumption, it should be used in poultry farms and piggery farms This is my suggestion ...(*Interrupitons*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): Please sit down.

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO: You are not allowing me to explain.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): You were not allowed to explain, you were allowed only to seek clarifications. You have made your points. Please sit down....(*Interruptions*) ....Yes, Mr. Bagrodia.

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO: Then there seems to be no purpose in seeking clarifications. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): You were to seek clarifications only, not to explain. Please sit down....(*Interruptions*)....Mr. Hanumantha Rao, you have taken more time.... (*Interruptions*)....

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO: Mr. Hanumanthappa has taken more time though I do not want to blame him. But you are stopping me...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): Now, Mr. Bagrodia.

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): Sir, there is one statement dated 22nd May, and, according to Mr. Hanumanthappa there is another one dated the 23rd May and there is still another one, dated 24th May, and all have come on the Ist of June. It means that there are three statements. Has the Government been sleeping over these for the past one week. You could not update these statements. You are only taking the House for ranted. It is a matter of shame. Anyway, whatever information you have given, on that I would like to make certain observations.

In the statement, it has been said that the Members may recall the huge loss of human life, numbering about ten thousand, during, 1977, but, because of the timely preventive measures taken, the loss of human life could be minimised. I wish you had mentioned that this was done by the Andhra Pradesh Government and not by the Central Government.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): You don't explain. You seek clarifications only.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: I am doing that only.

Sir, as Mr. Hanumanthappa pointed out, they have reduced the amount from Rs. 25,000/- to Rs.

15,000/-. If you can reduce it like that, tomorrow somebody else may donate ten thousand rupees and you will further reduce the amount to ten thousand rupees and the trust of the people in the Government would be lost in this way, the trust of the hapless people in Andhra Pradesh. Please don't do that. If at all you have to do anything, it is to increase the amount to Rs. 25,000/- if you want to maintain your credibility.

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO: It is unusual that people grudge giving relief to the sufferers, most unusual. Why do you grudge the relief given?

SHRI SANTOSH BAGRODIA: In the statement you have mentioned 50,000 tonnes of rice and 15,000 tonnes of phosphate fertilizer. I would like to know specifically as to what the State Government desired and by when these should be sent. Is there an overall shortage of rice and fertilizer in the country that you cannot supply enough quantities as are required there. When you say rain-soaked material will be taken which will be fit for human consumption, how do you ensure that it will continue to remain fit for human consumption? Have you set any time-limit by which all the insurance claims must be settled? Have you given any insurance claims Then, an 8-member Central team went there from 13th to 16th and still we do not know what measurs are suggested by them. I do not know what measures have been suggested. My last point: Have you involved any voluntary organisation or have any voluntary orgaisations come forward on their own and, if so, who are they?

SHRI MENTAY PADMANABHAM (Andhra Pradesh): This is a statement made on 24th, one week old. I would like to know from the honourable Minister whether he has any additional information from the Crisis Managemnet Group set up in the Department of Agriculture and Cooperation. In the statement he said they had set up a Crisis Management Group to monitor the position with regard to relief and restoration. Therefore, I want to know whether he has any additional information which can throw light on the relief and rehabilitation measures. My second question is whether the Government of Andhra Pradesh submitted its final report. My third question is this. It is stated in the statement that banks and public sector undertakings are adopting some villages and some areas for relief and rehabilitation. I would like to ask the honourable Minister as to how many villages or how many areas are being adopted by banks and public sector undertakings as of now. My fourth question is this. It is said that consumption loans will be given to the rural poor and that loans to cooperative societies will be rescheduled. In this connection I want to know whether any instructions have been given to the NABARD and the Reserve Bank of India not to take into consideration the overdue position of the cooperative societies wich have already given loans to various farmers, while giving relief of consumption loans to the rural poor. I also want the Minister to tell us about rescheduling of the loans given to the farmers.

Another point, Sir. The statement is one week old, but the situation has drastically changed in the area. The civil administration at the district level is in complete collapse. The relief operations are also over. About the rehabilitation of those people who have been evacuated from their homes, according to the statement, Sir. 6.5... (*Time bell rings*)

I would like to know from the hon. Minister how many people have been rehabilitated.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): Mr. Ram Naresh Yadav. Two minutes.

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं केवल सवाल ही

[श्री राम नरेश यादव]

करूंगा। पहला, इस वक्तव्य में कहीं पर इस बात का उल्लेख नहीं है कि कुछ समाजसेवी संस्थाओं ने भी इसमें आगे आकर अपना सहयोग किया है या नहीं किया है, ? और अगर किया है, तो उसका उल्लेख इसमें क्यों नहीं किया गया है? दूसरा, सरकार जो धान की खरीद करने जा रही है, उस धान की खरीद में सबसिडी देगी या नहीं देगी ? तीसरा, अभी बर्बाद होगई है, तो आगामी रबी की फसल की बुआई के लिए बीज, खाद, पानी और कीटनाशक दवाइयों के लिए सरकार क्या प्रबन्ध करने जा रही है ? चौथा, वहां जो गरीब लोग हैं, जैसे मछुआरे हैं या दूसरे लोग हैं, जिनकी जीविका का साधन चला गया है, उनके मकान चले गए हैं, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए सरकार क्या कर रही है ? पांचवां, चूंकि इससे बहुत बड़ी क्षति हुई है; इसलिए मैं यह भी जानना चाहूंगा, चूंकि किसान के पास कुछ नहीं रह गया है, उसकी फसल चली गई है तो क्या उसे सस्ते रेट पर ऋण सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा और अगर कराया जाएगा तो किस रेट पर कराया जाएगा ? छठवां, फाइनेंस कमीशन ने जो मानदंड निर्धारित किया है, उनके आधार पर केन्द्र सहायता देती है। इस संबंध में मैं जानना चाहूंगा कि वहां की भीषण स्थिति को देखते हुए क्या उसमें छूट देकर और अधिक अतिरिक्त व्यवस्था करने का फैसला सरकार करेगी या नहीं करेगी ? आखिरी प्रश्न, जो लोगों ने ऋण लिए हुए हैं, चूंकि फसल उनकी बर्बाद होगई है, और भारी क्षति हुई है, तो क्या उनको माफ करने के बारे में सरकार विचार कर रही है और अगर विचार कर रही है तो कब तक विचार कर लेगी ? धन्यवाद ।

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY (Andhra Pradesh): I want to raise some pointed questions, Sir. Relief operations have been discontinued since the 28th, which I also pointed out previously on the floor of this House. Now there are no relief operations. There are about 1500 camps and about six lakh people. Will the provisions and other commodities be supplied, even though the Central Government has supplied 50,000 tonnes of these, and 5000 tonnes of edible oil? Are they going to get the essential commodities. That is one very important question. Then, about agriculturists about whom it has been explained, and about insurance agencies coming into operation, are they coming into operation. Are they giving relief? That also has to be answered by the Minister, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI) : Thank you......(*Interruptions*)

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY: The farmers will have to plough the land. They have to start the agricultural operations. Now, with all the previous operations gone, how can can the farmers start the agricultural operationns? What about the inputs? Has the Government any information regarding the inputs? How is the Government, on such a vast area, with so much damage, going to help the farmers? (*Time bell rings*)

Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): Shri Swamy Naik.

श्री जी० स्वामी नायक (आन्ध्र प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आन्ध्र प्रदेश में नौ जिलों में तो भयंकर समुद्री तूफान की वजह से क्षति हुई हैं, यह क्षति सन् 1977 में जो तूफान आया था, उससे भी ज्यादा भयंकर क्षति हुई है। माननीय मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, यह 24 मई का स्टेटमेंट है और 24 मई के बाद आज पहली जून है, मैं जानना चाहूंगा कि इसके बाद आज तक और कितने लोग मरे हैं? और यहां से केन्द्रीय टीम जो गई थी वहां पर, उसके जो एसैसमेंट हुए हैं, उनके अनुसार कितना नुकसान हुआ है, इसकी भी जानकारी दें ?

मान्यवर, 9वें फाइनेंस कमीशन के नाम से पूरे वर्ष में नेशनल कलामिटी के लिए 86 करोड़ रुपए निर्धारित किए हुए हैं। मैं यहां पर देश के प्रधान मंत्री श्री विश्व-

नाथ प्रताप सिंह इसमें कोई दो रायें नहीं कि 12 और 19 मई को उन्होंने आन्ध्र प्रदेश का दौरा किया और उन्होंने अब तक सवा बत्तीस, सवा बत्तीस के दो इन्स्टालमेंट में चौंसठ, साढ़े चौंसठ करोड़ रुपए सैंक्शन करे हैं और यहां पर कम से कम तीन हजार करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया है, तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि हर साल आन्ध्र प्रदेश में इस तरह के तूफान आते रहते हैं, उसकी रोकथाम के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को क्या मदद देने जा रही है, इसकी जानकारी वे दें? इसी विषय में प्रधान मंत्री फंड से दो करोड़ रुपए दिए गए ।

वहां पर मछुआरों के जाल वगैरह का भी काफी नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान की पूर्ति के लिए क्या और भी कोई मदद करने वाले हैं ?

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): ओ०के० । मोहम्मद खालीलुर रहमान ।

श्री जी. स्वामी नायक: मान्यवर, आखिरी प्रश्न है । बहुत इम्पोरटैंट बात है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): इम्पोरटैंट बात आखिर में क्यों कह रहे हैं आप ?

श्री जी० स्वामी नायक: अभी मेरे तेलुगू देशम के मेरे साथियों ने वहां की राज्य सरकार जो काम कर रही है, राहत कार्य कर रही है, उसके लिए आक्षेप लगाए हैं कि डा० चेन्ना रेड्डी, जो वहां के मुख्य मंत्री हैं, वे वहां पर राहत का काम करने की बजाए अमरीका गए हैं और ऐसा इल्जाम लगाया गया है । डा० चेन्ना रेड्डी का अमरीका जाने का प्रोग्राम काफी पहले से बना हुआ है, इसलिए यह गलत है । वहां काम बराबर हो रहा है और उनकी दूरअंदेशी से जो काम हुआ है, उससे कम लोग मरे हैं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): सब उसकी तारीफ कर रहे हैं ।

Mr. Chenna Reddy is capable enough to defend himself.

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. UPENDRA): Sir, I am sorry to interrupt this business. In the morning. I proposed some business for the day. I had suggested that immediately after the legislative business. we would take up the reply to the Debate on Price Rise and then the Statement on Andhra Pradesh Cyclone. The Half-an-Hour Discussion will be taken up if there is time left. The Half-an-Hour Discussion has already taken place. The Members are seeking clarifications on the Statement on Andhra Pradesh Cyclone. Sir. I would like to know what you propose to take up next. As per the demand in the morining. the reply to the Debate on Price Rise has to be taken up. I do not know how many more Members would like to seek clarification on the Steel policy.

As per the demand made in the morning. I would request you to call the hon. Deputy Minister for Finance to reply to the Debate on Price Rise for a few months. After that you can take up clarifications on the Steel Policy.

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): I beg leave of you because I have to attend some urgent meeting. I will not be able to be present.

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): खलीलुररहमान जी, दो मिनट बोलियेगा ।

श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान (आंध्र प्रदेश) : जनाब, मैं दो मिनट ही लूंगा । मैं मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहूंगा कि इस जबरदस्त तूफान की वजह से वहां का जो एग्रीकल्चर लैंड है, उस एग्रीकल्चरल लैंड की जो समुन्दर के पानी और रेत की वजह से फर्टिलिटी मुत्तास्सिर हुई है, क्या हुकूमत इस बात पर गौर कर रही है कि इस फर्टिलिटी को दोबारा वापस लाने के लिये वहां

[श्री मोहम्मद खलिलुर रहमान]

के किसानों को कर्जा दिया जाय ? मेरा यह मशवरा है कि 15 से 20 हजार रुपये का कर्ज वहां के किसानों को दिया जाये।

मेरा दूसरा क्लैरिफिकेशन यह है कि खबर आई थी कि आंध्र प्रदेश के साइक्लोन को नेशनल कैलेमिटी डिक्लेयर किया जा रहा है। क्या हुकूमत इस बात पर संजीदगी से गौर कर रही है।

मेरा तीसरा क्लैरिफिकेशन यह है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया की जानिब से 84 करोड़ रुपये जो मंजूर किये गये हैं, क्या हुकूमत की जानिब में इसमें इजाफा किया जायेगा ?

मेरा चौथा क्लैरिफिकेशन यह है कि क्या यह सच है कि रियासते हुकूमत यानी वहां की स्टेट गवर्नमेंट अभी तक तूफान से होने वाले नुकसान की मुकम्मल तफसील हुकूमते हिन्द को नहीं भेज पाई है ? क्या यह सच है ?

ये मेरे चार क्लैरिफिकेशंस हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मंत्री जी इन बिन्दुओं पर जवाब दें।

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Mr. Vice-Chairman, Sir, the statement by the hon. Minister of State for Agriculture, though elaborate, does not give the details of the relief operations that have been carried out in Andhra Pradesh as far as the cyclone victims are concerned. Sir, I could see from the statement that the Crisis Management Group set up in the Department of Agriculture and Co-operation continues to monitor the position with regard to relief and rehabilitation. That being the the case, what were the further relief operations that have been carried out [illegible] was made on the 24th? The Government is silent on that. Sir, the Government should have come with additional information. I want a reply from the hon. Minister as to what further relief operations that have been carried out.

Secondly, Sir, for the persons [illegible] have died during the cyclone, [illegible] amount of Rs. 25,000 has been san[illegible] ned. A sum of Rs. 10,000 has [illegible] given from the Prime Min[illegible] Relief Fund and Rs. 15,000 fro[illegible] People's Natural Calamities [illegible] Sir, I would like to know [illegible] this amount of Rs. 10,000 fro[illegible] Prime Minister's Relief Fund i[illegible] Rs. 2 crores which was announc[illegible] the Prime Minister when he wen[illegible] Andhra Pradesh. Is it from that [illegible] not? Then, Sir, the Ninth Finan[illegible] Commission has outlined an amou[illegible] of Rs. 86 crores for Andhra Pradesh for the natural calamities. The funds provided by the Central Government [illegible] amount to Rs. 78 crores. Sir, the Prime Minister visited Andhra Pradesh twice. Now, it has been estimated by the Agriculture Ministry that the loss of agricultural produce amounts to Rs. 792 crores. That being the case, how can this amount of Rs. 78 crores compensate the loss which amounted to Rs. 792 crores during the cyclone?

Then, Sir, while coming to my state of Pondicherry, we claimed Rs. 5 crores from the Central Government for the natural calamity that has affected our state which is in the coastal area. But the Central Government has not provided sufficient funds. What is the reply from the hon. Minister on this point ?

Then, Sir, the cyclone affected areas in AP have been visited by the Chief Minister and also the Opposition Leader, Mr. N. T. Rama Rao. Sir, a canard and a false campaign has been raised by the Opposition Leader, Mr. N. T. Rama Rao that the State Government is not doing any relief operation. When the Central Government in its statement admitted that relief operations have been done very well by the State Government, this Opposition Leader is raising a canard and a false campaign against the State Government. It is unfortunate.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): Please conclude.

SHRI V. NARAYANASAMY: Therefore, I want the Telugu Desam Members to persuade the Opposition Leader in AP to withdraw his statement. (*Interruptiods*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): Mr. Malaviya. (*Interruptions*) Dr. Reddy, Please.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरे केवल दो प्रश्न हैं। आंध्र प्रदेश में 976 और तमिलनाडु में 7 व्यक्तियों की और दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई पांडिचेरी में। इस प्रकार से 985 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। तो मंत्री जी ने अपना जो वक्तव्य दिया है है उससे यह बात स्पष्ट नहीं है कि इस परिवार के जो आश्रित हैं उनको स्थाई रूप से बसाने के लिये क्या कदम उठाये हैं? और दूसरे, ऋण की वसूली, कर्ज की वसूली स्थगित की गयी है तो सरकार का कोई इरादा वहां पर कर्ज की माफी का भी है या नहीं?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): Before I call the next speaker, I would like to inform the House that because of the request made by the Minister of Parliamentary Affairs, after clarifications are sought on this and the Minister of State for Agriculture replies, the Deputy Minister of Finance will reply to the discussion on price rise. Then, in regard to the clarifications to be sought by hon. Members on the statement made by the hon. Minister of Steel and Mines, I would like to know from hon. Members whether they are prepared to sit to complete this item also

SOME HON. MEMBERS: We are prepared.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो एग्रीकल्चर सैक्टर में वहां पर क्रॉप की हानि हुई है उसका क्रॉप इन्श्योरेंस हुआ था या नहीं? दूसरा, वहां मवेशी या गाय जो काफी हद तक मर गयी है 22184 और 22950 और जो वहां बीमारी फैल रही है मवेशियों में भी उनको बचाने के लिये, उनकी रक्षा करने के लिये कितने वैटर्नरी डाक्टर काम में लगे हुये हैं? और वहां जो कालरा और एपिडेमिक फैल रही है इस साक्लोन के कारण उसके लिये वहां के हास्पिटलों में अभी बैड की आक्यूपैंसी का रेट क्या है? इसके अतिरिक्त मकान जो टूटे हुये हैं और इससे पहले भी वर्ष 1977 में दस हजार लोग मारे गये थे वहां कोस्टल एरिया में, स्ट्रांग स्ट्रक्चरल के मकान बनने चाहिये, उस तरह के डिजाईन बनाने की कोई सुविधा दी जा रही है या नहीं दी जा रही है? और मकान बनाने के लिये पचास हजार रुपये प्रति परिवार को वहां फिक्स पर्सेंट रेट आफ इंटरेस्ट पर कर्जा देना चाहिये।

तीसरा था, कि जो लोग मारे गये हैं, यहां दंगों में लोग मारे जाते हैं उनको एक-एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है, मेरी मांग है आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कि कम से कम प्रति मृतक के पीछे पचास हजार रुपये करके उनको दिया जाये।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): बस हो गया।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: दूसरा, सर, वहां के लोगों को अपना काम शुरू करने के लिये पच्चीस हजार रुपये से ऊपर से 6 परसेंट के रेट आफ इंटरेस्ट पर वहां पर कर्जा दिया जाय। तीसरे, वहां पर नेवी और पुलिस के लोगों को लगाया गया तो मैं जानना चाहता हूं कि स्टेट में सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दिये हुये ट्रेंड लोग हैं या नहीं? और उनको उसमें इंवोल्वड किया था या नहीं किया था? और केन्द्रीय सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने अभी तक उस इलाके का विजिट किया है या नहीं किया है? क्योंकि वहां बीमारी फैल रही है?

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया]

महोदय, मैं आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि वहां पर हालात ऐसे हो रहे हैं, वहां मुख्य मंत्री और वहां के विपक्ष के नेता दोनों ने इन इलाकों का दौरा किया है। किन्तु वहां की विपक्ष की पार्टी ने एक गन्दा सा माहौल बन दिया है और लोगों को भड़का रहे हैं। रिलीफ पार्टी के खिलाफ और एक आन्दोलन चल रहा है। इसकी भर्त्सना करनी चाहिये और इस पर रोक लग नी चाहिये, क्योंकि यह गवर्नमेंट के... (व्यवधान) रोकने की हर कोशिश कर रहे हैं... (व्यवधान) वहां पर... (व्यवधान) कौलर पकड़कर निकाला जा रहा है और यह विपक्ष की पार्टी वहां के लोगों को भड़का रही हैं। इस पर रोक लगानी चाहिये। धन्यवाद।

एक सम्मानित सदस्य : क्या बोल रहे हैं आप ?

डा रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंग कि 24 तारीख क स्टेटमेंट उसी रूप में हम लोगों को दिया गया है एक सप्ताह में। क्या मंत्री महोदय को इतना भी ध्यान नहीं था कि अपटूडेट स्टेटमेंट दें और उसी पुराने स्टेटमेंट को हम लोगों को क्यों इश्यू किया ? और मैं जानना चाहता हूं कि कुल 792.78 करोड़ रुपये कृषि का नुकसान हुआ है और क्षतिग्रस्त मकान 9.19 लाख हैं और इसमें कहा गया है कि आगे की विभिन्न आवश्यक एवं वित्तीय व्यवस्था करने वाली एजेंसीज से अनुरोध किया गया कि वे चक्रवात में ढह गये मकानों के स्थान पर पक्के मकान तैयार करने के लिये उदार शर्तों पर ऋण सुविधायें प्रदान करें।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : पढ़िये मत, पढ़िये मत।

डा रत्नाकर पाण्डेय : जब बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है तो ऋण क्यों लेंगे। उनके लिए सरकार चाहे वर्ल्ड बैंक से कर्ज ले चाहे कहीं और से लेकिन सब के लिए आवास की व्यवस्था करे, सब के कुशल क्षेम की व्यवस्था करे। इस पर मंत्री महोदय को क्या कहना है वह बतायें। एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं कि दूर-संचार, सड़क, परिवहन, बिजली, रेलवे से संबंधित क्षति का भुगतान लगाने और मरम्मत/पुनर्स्थापन कार्य करने के लिए विभिन्न केन्द्रीय विभागों द्वारा कार्यवाही दलों का गठन किया गया है तो जो अनिवार्य सेवायें हैं क्या वह केन्द्रीय सरकार द्वारा चालू हो गई हैं और नहीं चालू हुई हैं तो क्यों नहीं हुई हैं ? अंत में कहना चाहूंगा कि जहां बाढ़ आती है, वृष्टि होती है, जहां तूफान आता है वहां पतन होता है तो स्टेट गवर्नमेंट ने केन्द्रीय सरकार से कितनी सहायता मांगी है और आपने कितनी सहायता दी है यह मैं जानना चाहूंगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर (मध्य प्रदेश) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं तीस सेकिण्ड या एक मिनट में अपनी बात कहना चाहूंगा। मेरा सिर्फ सवाल यह है कि जहां साइक्लोन आया है जिससे 14 जिले प्रभावित हुए हैं उससे सबसे ज्यादा अगर किसी कम्युनिटी को नुकसान हुआ है तो किसान को हुआ है, उन की फसलों का हुआ है, उनके मवेशियों का नुकसान हुआ है। यह इन्होंने स्पेसिफिक रूप से नहीं बताया कितना हुआ है मैं चाहूंगा मंत्री महोदय इसे बतायें। आखिर में लिखा है कि कृषि तथा अन्य सार्वजनिक सेवाओं को पहुंची क्षति 792.78 करोड़ की है। यह बताइये कि कृषि से संबधित जो नुकसान हुआ है जिसमें फसल भी आती है, जिनका किसानों से संबंध है, वह कितना हुआ है और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि इस देश में सबसे दुर्भाग्यशाली कोई है तो वह किसान है। उसका जितना नुकसान हुआ क्या सरकार उसकी भरपाई कर पायेगी ? मैं दूसरा सवाल मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं यह जो पशु, भेड़-बकरियों और कुक्कुटों के बारे में लिखा है क्या उनकी क्षति पूर्ति करने की कोई योजना है ? अंत में एक बात मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि अपने वक्तव्य के 10वें नम्बर पर कहा है कि वर्षा के पानी से भीगे, मलिन हो गये धान तथा चावल की खरीद और मानदंडों में ढील

दी गयी है तो मेरा इस पर ग्राब्जेक्शन है। यह जो ढील दी गयी है इस ढील में क्या ऐसे ग्रनाज को खरीदा जायेगा जिस को दूसरे लोग ग्रगर उपयोग में लायेंगे तो उनको ग्रपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा ऐसी कोई योजना है कि इसको वापस लिया जा सके ?

डा० ग्रबरार ग्रहमद खान (राजस्थान) : मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ग्रभी खलीलुर रहमान साहब ने एक सवाल उठाया था बहुत महत्वपूर्ण है . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : उन्होंने जो सवाल पूछा था उसे छोड़िये। ग्रपना सवाल पूछिये।

डा० ग्रबरार ग्रहमद खान : मैं उसी से संबंधित सवाल पूछ रहा हूं। वहां जो तूफान की वजह से समुद्र के पानी ग्रौर रेत से जो कृषि भूमि बेकार हो गई है, फर्टीलिटी खत्म हो गई है उसके लिए वह रिवाइव की बात पूछ रहे थे लेकिन मैं इसके साथ यह भी जानना चाहता हूं कि ऐसी कितनी भूमि है जिसकी फर्टीलिटी खत्म हो गई है ग्रौर उस फर्टीलिटी को रिवाइव करने के लिए सरकार कोई कदम उठा रही है ? यदि उठा रही है तो वह क्या है ?

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI (Gujarat): I would like to have a clarification with regard to para 4, item No. 12, where in the damage to agriculture, other public utility services has been to the tune of Rs. 792·78 crores. I would like to know, what is the total loss during this particular cyclone in Andhra Pradesh and Tamil Nadu so far as these two items are concerned? This has not been clarified.

In para 7 it is said that our Prime Minister has given Rs. 2 crores, Rs. 32·25 crores and another amount of Rs. 32·25 crores is to be paid to the respective States. I would like to state that on 11th May it was stated that the Centre would give assistance to the extent of 75 per cent of the total damage. Why has 75 per cent not been given? In respect of para 10, it has been said that the institutions like Insurance agencies and other local bodies have been directed to assist and report. What aid has been given by those agencies, that may also be clarified.

SHRI J. S. RAJU (Tamil Nadu): Sir, according to the press reports, the loss of human lives is 13, but in the statement made by the honourable Minister it is mentioned as seven. I just want to know whether it is seven or 13.

श्री नितिश कुमार : महोदय, बीस माननीय सदस्यों ने इस वक्तव्य पर ग्रपना स्पष्टीकरण पूछा है। सबसे पहले यह पुराना वक्तव्य है, इसकी चर्चा माननीय सदस्यों ने की है। सदन इस बात से ग्रवगत है कि मैं पिछले सप्ताह वक्तव्य देना चाह रहा था ग्रौर श्री ग्रहलूवालिया जी ग्रच्छ तरह से जानते हैं कि वक्तव्य क्यों नहीं दिया जा सका। ग्राप भी चेयर पर थे यह बात हुई थी कि सोमवार को ग्राएगा। तब से मैं प्रतीक्षा में था कि कब यह बात ग्राएगी। ग्राज ग्रचानक सूचना मिली कि उस पर क्लेरीफिकेशन्स लिये जायेंगे। उसके चलते यह पुराना वक्तव्य हो गया। ग्रगर कहीं से इस सदन में ग्राने से पहले यह जानकारी होती कि मुझे इस स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा तो मैं बिलकुल ग्रप टू डेट ग्राज दोपहर तक की स्थिति का उसमें जिक्र करता। लेकिन मुझको जानकारी थी कि उसी पुराने वक्तव्य पर क्लेरिफिकेशन्स पूछे जायेंगे। इसलिए मेरे पढ़ते वक्त ग्रापने गौर किया होगा, एक दो जगह मैंने स्वयं सुधार किया। पैरा 7 में जो टाइप्ड है उसमें लिखा था—राज्य सरकार द्वारा पहले निर्मुक्त की गई राशि व्यय कर लिये जाने पर 32.25 करोड़ रुपये की शेष राशि भी तत्काल निर्मुक्त कर दी जाएगी। मैंने उसमें संशोधन करके कहा कि 28–5–90 को 32 करोड़ 25 लाख रुपये की शेष राशि भी तत्काल निर्मुक्त कर दी गई है।

जहां तक तमिलनाडु के संबंध में सवाल किया गया है कि डेथ 7 या 13 हैं। मैंने ग्रपना वक्तव्य पढ़ते वक्त कहा कि तमिलनाडु की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक मृतकों का फीगर 13 हो चुका है। मैं

[श्री नितिश कुमार]

इसके लिए क्षमा चाहता हूं कि अंतिम समय में जानकारी मिली कि मुझे सुओ मोटो स्टेटमेंट देना है, आप टू डेट स्टेटमेंट मैं नहीं दे सका। पुराना स्टेटमेंट था उसी को मैंने पढ़ा है। नई बातों को मैं क्लेरिफिकेशन के दौरान बताऊंगा। सब से पहले मृतकों की संख्या की सफाई दे रहा हूं। कई सदस्यों ने कहा कि पुरानी रिपोर्ट है और आन्ध्र प्रदेश के बारे में 976 डेथ हुई हैं। लेकिन सदन की सूचना के लिए मैं कहना चाहता हूं कि अब आन्ध्र प्रदेश सरकार से जो रिपोर्ट मिली है जो डेमेज उन्होंने दिखाया है उसके बारे में कहा गया कि अलग-अलग कुछ नहीं बताया गया है। सदन के पास अपना बिजनेस है। नहीं तो मेरे पास पूरी रिपोर्ट है कि किस किस क्षेत्र में क्या हुआ है जैसे कृषि हो, चाहे बागवानी हो, सड़क हो, चिकित्सा हो, किस क्षेत्र में कितनी क्षति हुई है, उसको अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पढ़ सकता हूं कि किस क्षेत्र में कितना नुक्सान हुआ है, उसको लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि जो वक्तव्य दिया गया है उसके बाद आन्ध्र प्रदेश की सरकार की तरफ से अभी तक कोई विस्तृत विवरण जो हो सकता है वह नहीं मिला है। जो कुछ मिला है वह यही मिला है कि राज्य सरकार ने 30-5-90 को एक टैलेक्स मैसेज के द्वारा सूचित किया है कि कुल मृतकों की संख्या पहले 976 दी गई थी। उसमें उन्होंने कंफर्म किया है कि 817 निश्चित रूप से मरे हैं और 150 मृतक व्यक्तियों के बारे में ब्यौरा उनको मिला है जिनके बारे में वे जांच कर रहे हैं और जिला अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि ये फेक फीगर्स हैं या जेन्युअन फीगर्स हैं। मृतकों की संख्या 976 थी, अब 817 है राज्य की रिपोर्ट के मुताबिक और 150 के बारे में वे जांच करवा रहे हैं।

कई माननीय सदस्यों ने प्रोक्योरमेंट के बारे में कहा गया है। एक माननीय सदस्य ने इस पर एतराज भी किया। अगर उन्होंने मेरे वक्तव्य को सफाई से पढ़ा होता तो उनको पता चलता कि उसमें लिखा है कि वह खाने योग्य रहे। जो जरूरी नार्म्स हैं वे एक सीमा तक ही रिलैक्स किये जाते हैं, खाने योग्य रहे, इनहाइजिनिक नहीं रहे, हाइजनिक रहे, इसको देखा जाता है। उन्होंने यह सवाल उठाया, इसलिए सुविधा के लिए और किसानों को राहत पहुचाने की दृष्टि से खरीदा जाता है। जो अब तक खरीद हुई है, जो मैसेज आज मिला है उसके मुताबिक 30 मई, 90 तक 13586 टन धान का प्राक्योरमेंट हुआ है और 31807 टन चावल की खरीद की गई है। अधिक से अधिक खरीद के लिए बार बार यहां से कहा जा रहा है। मैं सदन को बताना चाहता हू कि आज ही उप-प्रधान मंत्री एवं कृषि मंत्री चौधरी देवी लाल से आंध्र प्रदेश के कुछ संसद सदस्यों का एक शिष्ट मंडल मिला था। यहां पर माननीय सदस्यों ने इस सवाल को नहीं उठाया लेकिन वहां यह सवाल उठाया गया था कि प्रोक्योरमेंट के बारे में ठीक से, मुस्तैदी से काम नहीं हो रहा है। इस संबध में पुनः निर्देश दिये जा रहे हैं और सख्ती से अधिक से अधिक खरीद की जायेगी। जो किसान इस लायक बच गये हैं और नार्म्स को जितना रिलैक्स किया गया है उसके अन्तर्गत जो आयेंगे उन से खरीदने के लिए एक एफ० सी० आई० को बराबर निर्देश दिया जा रहा है।

कुछ माननीय सदस्यों ने मकान आदि के संबंध में सवाल उठाये हैं। वहां पर आंध्र प्रदेश में हुडकों के चैयरमैन गये थे प्रधानमंत्री के निर्देश के आलोक में और वे आंध्र प्रदेश सरकार से बात करके लौटे हैं। वहां पर 1 लाख मकान हुडको बनायेगा। मकान कितने गिरे हैं इसकी फिगर्स उद्धृत की जा चुकी है। लेकिन एक लाख पक्के मकान हुडको बनायेगा, इसमें सहमति हो चुकी है। इस पर 90-95 करोड़ रुपये के आस-पास व्यय होगा। प्रारम्भिक आंकलन के मुताबिक फिलहाल 11 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी है। बाकी रकम कैपिटल मार्केट से, कसोटेरियम के द्वारा ... (व्यवधान) ... 90-95 करोड़ रूपये वह ब्यौरा है जो हुडको खच करेगा। बाकी अरेंज करने का प्रयास कर रहे हैं।

यहां पर इस बात की भी चर्चा हुई कि जो राहत केन्द्र सरकार के द्वारा पहुचाई

है वह नाकाफी है। महोदय, नाइंथ स कमीशन के रेकमन्डेशन के अनुर राज्य के लिए अलग अलग कैलामटी ना दिया गया है। लगभग 805 रुपये का रिलीफ फंड, 25 राज्यों अलग अलग बना है। इसमें आंध्र लिए 86 करोड़ रुपये हैं। इसमें नशन केन्द्र का हिस्सा है और बाकी तिशत राज्य सरकार का हिस्सा है। सरकार का जो 75 प्रतिशत हिस्सा 64 करोड़ 50 लाख रुपया वह केन्द्र रिलीज कर दिया गया है। अब जहां क अतिरिक्त सहायता का सवाल है इसके संबंध में नाइंथ फाइनेंस कमीशन की रेकमेंडेशन है और इसके मुताबिक इस पर और किया जा रहा । यह जो कैलामटी रिलीफ फंड है वह इसलिए बनाया गया है क्योंकि जब भी जरुरत होती थी तो राज्य सरकारें केन्द्र की ओर दौड़ती थीं और वहां पर बार बार सेंट्रल टीम जाती थी, वे असिसमेंट करते थे अलग अलग मामले पर निर्णय होता था। इस चीज से बचने के लिए कैलामटी रिलीफ फंड बनाया गया है और 75 फीसदी उसमें केन्द्र का हिस्सा है। आंध्र में तूफान आया तो केन्द्र सरकार ने अपना पूरा हिस्सा रिलीज कर दिया है। बाकी पैसा आंध्र प्रदेश सरकार को देना है, 25 प्रतिशत देना है। इतने बड़े पैमाने पर यह क्षति हुई है जिसको आंका नहीं जा सकता। बड़े पैमाने पर क्षति हुई है, इसमें दो राय नहीं हो सकती । हमें राजनीति से ऊपर उठकर ऐसे मसलों में..

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : खुदा न करे फिर आंध्र प्रदेश में कोई ऐसी कैलामटी हो जाय तो आप जो नाइंथ फाइनेंस कमीशन का पैसा है उसको भी आप टोटली एक्जास्ट कर चुके हैं, तो कल कुछ ऐसी बात हो जाती है तो आप क्या करेंगे ?

श्री शिवराज पाटिल : माननीय सदस्य जो पूछ रहे हैं तो जब इतनी बड़ी विपदा आयेगी तो केन्द्र सरकार हाथ रोककर नहीं रह सकती । जो भी उसके पास है, जो आंध्र का हिस्सा होगा वह उसको रिलीज करेगी, यह केन्द्र सरकार का फर्ज है। जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं कल भगवान न करे ऐसा हो लेकिन अगर ऐसा होता है तो यह समूचे देशसवासियों का दायित्व है, यह सोचना हम सब का और सरकार का दायित्व है। उस विपत्ति की घड़ी में हम सब लोग मिलकर उस विपत्ति का मुकाबला करेंगे। इसमें आप और हम सब मिलकर राहत पहुंचाने के लिए जो कुछ भी संभव होगा, वह करेंगे।

यह जो राशि बची है यह राज्य सरकार को देनी है। मैंने जैसे कहा कि अब इससे उसकी भरपाई नहीं हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह जो रुपया दिया गया है रिलीज का, उससे पूरे नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती है। उनको मदद देने के मामले में अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री वहां गये थे तो उन्होंने वहां पर कई निर्देश दिए रिलीफ के मुताल्लिक। मैं इस समय यहां पर उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता हूं। महोदय जिन सवालों को माननीय सदस्यों ने उठाया है उनका जबाव देकर मैं समाप्त कर दूंगा। लेकिन एक बात जो वहां कही गयी कि इसमें और सहायता मिलनी चाहिये, तो इसके लिये प्रधान मंत्री जी ने निर्देश दिया कि इसको इक्जामिन करें। इक्जामिन करने के लिये एक एक्सपर्ट ग्रुप भी यहां बना हुआ है। प्रधान मंत्री जी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक बैठक 24 मई को विभिन्न विभागों की बुलाई। तो इस पर चर्चा हो रही है, विचार हो रहा है। लेकिन इन्तजार किया जा रहा है, आन्ध्र प्रदेश सरकार की रिपोर्ट का। जो उनकी रिपोर्ट है, उनकी जरूरत है, आवश्यकता है, इसके बारे में जब वे पूरी रिपोर्ट दे देंगे और वाजिब रिपोर्ट दे देंगे, तो इसके बाद भी उस पर विचार होगा। एक्सपर्ट कमेटी बनी हुई है, उसके बाद उनकी रिपोर्ट पर विचार करेगी, उस लास को असेस करेगी, तब आगे की कार्यवाही हो सकती है। जो संभव होगा, उसको केन्द्र सरकार करने का प्रयास करेगी।

मैं गुजारिश करना चाहूंगा और जैसा मैंने पहले कहा कि ऐसे विपत्ति के काल में हम लोगों को राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिये। एक माननीय सदस्य

[श्री नितिश भारद्वाज]

ने उठकर कह दिया कि मैंने अपने पूरे वक्तव्य में आन्ध्र प्रदेश सरकार की प्रशंसा नहीं की । शायद उनकी नजर से ओझल हो गया होगा, उन्होंने देखा नहीं होगा, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि पैरा 6 देख लें—"आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने निचले इलाके के लोगों को निकालने में समय से कार्यवाही की" यह आन्ध्र प्रदेश की प्रशंसा ही है। जो कुछ भी आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने किया उसका इसमें उल्लेख किया गया है । अपनी तरफ से केन्द्र सरकार ने इस पर कोई राजनीति करने का प्रयास नहीं किया है । जो भी संभव हुआ किया । दो बार प्रधान मंत्री जी गये और उन्होंने निर्देश दिया और उन निर्देशों के आलोक में तत्काल कार्यवाही की जा रही है।

जो आपने स्पष्टीकरण मांगे हैं और कृषि के बारे में जो कहा कि जमीन खराब हो रही है या किसानों को और क्या राहत दी जा सकती है .... (व्यवधान)

SHRI SANTOSH BAGRODIA: He doesn't say. He is making a wrong statement.

SHRI NITISH KUMAR: Why? How?

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Para 6 does not say. I don't understand this English. I have got the English translation. Here he does not say anything about the Andhra Pradesh Government.

SHRI MENTAY PADMANABHAM: In spite of all his mistakes the Minister is giving praise to the Andhra Government. (*Interruptions*)

श्री नितिश कुमार : मैं सुन रहा हूं, बताइये जरा।

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY: It says the Andhra Pradesh Government took timely action.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): The Minister is capable enough. He will reply. Don't interrupt.

श्री सन्तोष बागड़ोदिया : आपने अभी कहा कि आन्ध्र प्रदेश सरकार के लिये हमने आब्जेक्शन किया । आपने कहीं उनकी बड़ाई नहीं की । आपने कहा, नहीं, की है ? लेकिन इसमें कहीं नहीं है ।

श्री नितिश कुमार : इसमें पैरा 6 देखा जाये ।

श्री सन्तोष बागड़ोदिया : मैं पैरा 6 ही देख रहा हूं, इंग्लिश वाला देख रहा हूं ? हिन्दी में है, तो पता नहीं ।

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI P. SHIV SHANKER): It says: "The Members may recall the huge loss of human lives numbering 10,000 during the 1977 cyclone in Andhra Pradesh. However, because of the timely preventive measures, the loss of human lives could be minimised this time."

SHRI H. HANUMANTHAPPA: One minute, please. I am the man who raised that objection. I mentioned that in your paragraph 6, in the last line you say: "Their efforts are praise worthy."

SHRI NITISH KUMAR: So?

SHRI H. HANUMANTHAPPA: It is about the Meterological Department. In your Para 12, you say.....(*Interruptions*) You don't have the courtesy to say: the State Government. That was my objection.

श्री नितिश कुमार : मैंने जो स्टेटमेंट पढ़ा है, आन रिकार्ड वही है..... (व्यवधान)

श्री सन्तोष बागड़ोदिया : हिन्दी में होगा, अंग्रेजी में नहीं है ।

श्री नितिश कुमार : मैं हिन्दी में बोल रहा हूं । हिन्दी में है । अंग्रेजी में अगर कोई गलती होगी तो उसको

ार लिया जायेगा। पता नहीं कहीं ी स्टेज में गलती होगी।

श्री पी० शिवशंकर: अंग्रेजी में टेटमेंट है कि—

"On receipt of warning from the Meteorological Department ...ding the cyclone, the State ...ernment of Andhra Pradesh took ...y action in evacuating the people ...n the low-lying areas."

...ा ही लिखा हुआ है।

श्री नितिश कुमार : यह जो मैंने स्टेटमेंट दिया है, इस हाउस में... (व्यवधान)

SHRI MENTAY PADMANABHAM : What is wrong in it. (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI) : Please sit down. I have not allowed you to speak.

श्री नितिश कुमार : महोदय, अंग्रेजी वर्शन में वह मेंशन छूट गया हो, तो उसके लिये मैं क्षमाप्रार्थी हूं।

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Sir, ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI) : No, Dr. Sivaji. Please, no

श्री पी० शिव शंकर : आप जहां फरमा रहे हैं। पैराग्राफ 6 में जहां आप शुरू करेंगे वहां देखिये

(*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI) : No. It will not end that way.

अच्छी चीज बड़ी मुश्किल से दिखती है। अच्छा आगे चलिये।

SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL (Punjab) : One minute, Sir.

श्री नितिश कुमार : अब यह बात हो गयी कि इसमें आन्ध्र प्रदेश सरकार की चर्चा हम लोगों ने की है.... (व्यवधान) अब तो क्लैरीफिकेशन इतनी बार हो ही गये हैं, उनका जबाब तो सुन लीजिये।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : आपने कहा है कि —

"Para 7 starts : Our Prime Minister visited cyclone affected areas. Para 8 says : The Deputy Prime Minister and Agriculture Minister has already provided financial assistance."

वहां पर "अवर" है, यहां पर "दी" है, इसका कोई फर्क समझायेंगे कि यह क्या है।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : आपके मंत्री बहुत होशियार हैं। यह जबाब दे सकते हैं। आप फिक्र मत करिये।... (व्यवधान) ...

श्री नितिश कुमार : महोदय, मैं जानकारी दे रहा था कि जो सवाल उठाया गया कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से, कृषि विभाग की तरफ से, जो खेतो का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, जमीन खराब हुई है, इस संबंध में क्या किया जा रहा है?

एग्रीकल्चर, कोआपरेशन डिपार्टमेंट की तरफ से राज्य सरकार को कुछ हिदायतें दी गई हैं, सलाह दी गयी है, कि आप इनका पालन करें, किसानों तक इन बातों को पहुंचायें और कृषि विभाग प्रतीक्षा कर रहा है कि वहां से कोई वह कंटिन्जेंसी प्लन न बना करके हमारे पास भेजेंगे, ताकि उनकी संभव सहायता, मदद की जा सके। वहां से रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है और हम लोगों ने उनको सलाह दी है, कि कंटीजेंसी प्लान बनाइये, आकस्मिक योजना बनाइये और उस आकस्मिक योजना को यहां पर बनायेंगे, तो उस पर हम विचार-विमर्श करके जो भी संभव मदद होगी, वह की जायेगी, क्योंकि रिलीज का सवाल, रिलीज का वितरण है, या उसको मुहैया करने का सवाल हो, यह राज्य सरकार का मामला है। यह ...ि, बागवानी तम म ...र ज्य सरका की चीज है। हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं लेकिन एग्जाक्यूट करने का काम राज्य सरकार का है।

[श्री नितिश कुमार]

हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार सक्षम होगी, जो रिलीफ दिये जा रहे हैं, जो वहां लोगों की जरूरत है, उसके मुताबिक उनको राहत पहुचाने में, लेकिन अगर कोई शिकायत रह गई है, तो यह राज्य सरकार के स्तर पर भी इस बात को किया जा सकता है ।

माननीय सदस्यों ने चर्चा की कि वहां पर जो साइक्लोन अफैक्टेड लोग थे, उन पर गुंटूर जिले में गोली चली । ऐसी और भी चीजों की उन्होंने चर्चा की । अगर साइक्लोन अफैक्टेड लोगों पर गोली चली है, तो किस परिस्थिति में गोली चली, क्या कारण थे, हम लोगों के पास कोई वैसी जानकारी... (**व्यवधान**)...

SHRI MENTAY PADMANABHAM :*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI) : Not allowed. Nothing will go on record.

श्री **नितिश कुमार** : गोली किस परिस्थिति में चली, उसके बारे में हम लोगों को सूचना नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर साइक्लोन अफैक्टेड लोगों पर गोली चली है, तो वह दुर्भाग्यपूर्ण है, और सबको मिल कर लोगों को राहत पहुंचाने का काम करना चाहिए, प्रशासन को भी संयम बरतना चाहिए और इस परिस्थिति में जितना नुकसान हुआ है, जो आदमी पीड़ित है, स्वाभाविक है कि वह अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहेगा और मांगेगा ।

मैं चर्चा कर रहा था कि प्रधान मंत्री के निर्देश के मुताबिक, चाहे वह हुडको हो, हाऊसिंग बैंक हो, या व्यापारिक बैंक हो, सब को कहा गया है कि आप तुरंत पक्का मकान बनाने की व्यवस्था करें।

कई माननीय सदस्यों ने बीज आदि का भी सवाल उठाया है तो इस संबंध में प्रधान मंत्री ने निर्देश दिया है, राज्य सरकार को बता दिया गया कि राष्ट्रीय बीज निगम और स्टेट फार्म्स में कितने बीज किस-किस प्रकार के उपलब्ध हैं ; इसकी वह सूचना दें उनको हर संभव सहायता प्रदान जाएगी, यह भी प्रधान मंत्री का निर्देश

जैसा कि मैंने बताया कि क्रॉप प्लान बनाने का उन लोगों से किया गया है और जो प्रधान मं निर्देश भी था, और मैंने आपको दिया है कि जो भीगे हुए धान थे, मा नार्म्स रिलैक्स करके, उसको खरीदा गय

कुछ माननीय सदस्यों ने सवाल उठा कि इतना बड़ा नुकसान हुआ, रेल की पटरि और सड़कें ध्वस्त हुई और दूर संचार क व्यवस्था ठप हुई, तो इस संबंध में अभी तक क्या प्रगति है ?

तो मैं सदन को बता देना चाहता हू कि समालकोट और विशाखापटनम रेलवे पटरियों के टूट जाने के कारण परिवहन में गंभीर रूप में बाधा उत्पन्न हो गई है । डाऊन लाईन ठीक कर दी है, अपलाईन 5 जून तक चालू हो जाएगी, सिवाये गोलाप्रोलु से रावीवलपाडु सैक्शन के, जिसके 15 जुलाई तक चालू होने की संभावना है । रेल पटरियों को हुई अन्य सभी क्षतियों को कुल मिला कर पुनर्स्थापित कर दिया गया है ।

अब जहां तक दूर संचार का सवाल है, दूर संचार द्वारा गठित दल ने 14a5a1990 को आंध्र प्रदेश का दौरा किया था । क्षतिग्रस्त लाइनों, एक्सचेंजों के 93 प्रतिशत भाग को ठीक कर दिया गया है और शेष की स्थिति भी सामान्य हो जाएगी ।

जहां तक राजमार्गों का सवाल है, भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा गठित वर्किंग ग्रुप ने 15 मई को आंध्र प्रदेश का दौरा किया था। नेशनल हाईवे-5 यातायात के लिए पूर्ण रूप से चालू हो गया है । सालूर शहर के नगरपालिका क्षेत्र में आने वाला पुल भी क्षतिग्रस्त होने से राष्ट्रीय राजमार्ग–43 अभी भी आंशिक रूप से प्रभावित है । वहां रेस्टोरेशन का काम प्रगति पर है । उसके रेस्टोरेशन के लिए तत्काल 50 लाख रुपए की धनराशि पहले ही रिलीज की जा चुकी है और स्थाई उपाय अपनाने पर भी विचार किया जा रहा है ।

†Not recorded.

महोदय, मैंने चर्चा की कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को ऋणों को सस्पेंड करने, कनवर्ट करने और रिशेड्यूल करने का निर्देश दिया है । रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने ही निर्देश दिया है । इसलिए माननीय सदस्य जो स्पष्टीकरण पूछने जा रहे थे उस संबंध में विस्तृत निर्देश दिया गया है । इस योजना की प्रगति की समीक्षा करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर बैंकिंग सलाहकार समितियां नियमित रूप से बैठक करती रही है । शीर्ष बैंकों के मार्गदर्शन के तहत सभी बैंक राज्य और जिला अधिकारियों के साथ निकट संपर्क में काम कर रहे हैं ताकि इस मामले में सभी प्रकार की आवश्यक सहायता दी जा सके । इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं या राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, उन को निर्देश दिया गया है कि राहत कार्यों के लिए उस क्षेत्र को, शहर को, गांव को अपनाएं । सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों की रिपोर्ट प्राप्त हो रही है कि वे जिलाधिकारियों की सलाह से गांवों और शहरों को अपना रहे हैं और खाद्य सामग्रियों के पैकिट्स, बर्तन, कपड़ा और दवाइयों इत्यादि के वितरण में भी उनके माध्यम से काफी सहायता मिली है और उन लोगों को और भी राहत पहुंचाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं ।

महोदय, इस तरह से मैं समझता हूं कि जो कुछ भी सरकार की तरफ से किया गया है, यह कितना भी किया जाय कम ही कहा जाएगा । लेकिन अब तक जो किया जाता रहा है उससे अधिक तत्परता के साथ किया गया है । मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी दो बार गए हैं और 7 तारीख को इसी माह उप-प्रधान मंत्री जा रहे हैं । जो कुछ भी राहत दी गयी है, जो कुछ भी किया जा रहा है और उन को और क्या मदद की जरूरत है, क्या स्थिति है, क्या प्रगति है, यह जायजा लेने के लिए उप-प्रधान मंत्री एवं कृषि मंत्री 7 जून को आंध्र प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं ।

... (व्यवधान) ...

अब दो-तीन और सवाल हैं, जिनकी सफाई मैं देना चाहता हूं । एक माननीय सदस्य ने गुजरात के बारे में सवाल उठाया है ... (व्यवधान) ...

डा० शंकर पाण्डेय : राजीव गांधी का नाम भी लेना चाहिए । अपोजीशन के लीडर गए हैं, उनका नाम नहीं ले रहे हैं । देवीलाल जी और वी०पी० सिंह का नाम बार-बार दोहरा रहे हैं । यह खुली सरकार है इसलिए खुलकरके नाम लेना चाहिए ।

श्री नितिश कुमार : वह तो आप ले ही रहे हैं । आपने सदन को सूचना दे ही दी पाण्डेय जी । ठीक किया, आप का काम तो हो ही गया ।

गुजरात के संबंध में माननीय सदस्य ने सवाल उठाया था कि वहां के पंचमहल जिले में 6 लोग मारे गए हैं । इस संबंध में हमारे रिलीफ डिवीजन को किसी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं है ।

श्री अन्तराय देवशंकर दवे : आपने कहा था, सूचना मंगवा रहे हैं... (व्यवधान) ..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI) : You seek my permission before you speak. Otherwise, your speech will not go on record.

श्री नितिश कुमार : इस सायक्लोन से संबंधित जितनी भी सूचनाएं रिलीफ डिवीजन को मिली हैं, चारों तरफ से एकत्रित कर उन सूचनाओं को मैं सदन के समक्ष रख रहा हूं । अभी तक हमारे रिलीफ डिवीजन को गुजरात में, जिसका हवाला माननीय सदस्य ने दिया है, उसकी कोई जानकारी हम लोगों को नहीं मिली है । अगर गुजरात में इस तरह का कोई हूमन लास हुआ है, गुजरात में नुकसान हुआ है, उड़ीसा में नुकसान हुआ है, यह बात उस सदन में उठायी थी, तमिलनाडु के संबंध में भी उठी थी—तो तमिलनाडु से कोई रिपोर्ट नहीं है, उड़ीसा से कोई रिपोर्ट नहीं है, गुजरात से कोई रिपोर्ट नहीं है । पांडिचेरी से प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हम लोगों को प्राप्त हुई थी, उस में बहुत ज्यादा लास का जिक्र नहीं था । कहा गया था कि विस्तृत रिपोर्ट बनाकर

[श्री नितिश कुमार]

भेजिए। कहा गया है कि अब विस्तृत रिपोर्ट बनाकर के भेजिए ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं बता देना चाहता हूं कि कितने करोड़ रुपए का केलेमिटी रिलीफ फंड है, गुजरात का यह केलेमिटी रिलीफ फंड 85 करोड़ रुपए का है और वहां की सरकार अपने रिलीफ मेन्युअल के मुताबिक सहायता पहुंचाने में सक्षम है । केन्द्र सरकार का जो केलेमिटी रिलीफ फंड का 75 प्रतिशत रुपया है, वह केन्द्र सरकार देने को तत्पर है। गुजरात सरकार चाहे तो वह अपने नार्मस के मुताबिक उनको मुहैया करा सकती है । इसी तरह उड़ीसा की सरकार कर सकती है, यह तमिलनाडु की सरकार कर सकती है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। केलेमिटी रिलीफ फड इसीलिए बना है ।

महोदय, यह 25 हजार रुपया प्रति मृतक परिवार को देने के संबंध में कहा गया । मैं बताना चाहूंगा कि उप-प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, जो पीपुल ट्रस्ट है... (व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : आप क्लेरिफिकेशन तो मांगते हैं, फिर जवाब सुनते नहीं हैं । मंत्री महोदय, माननीय सदस्य संतुष्ट हो चुके हैं।

श्री नितिश कुमार : महोदय, इसको कहकर खत्म कर देता हूं । इंडियन पीपुल नेचुरल कैलेमिटी ट्रस्ट से माननीय उप-प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री, जो कि उसके पदेन अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने घोषणा की थी कि 25 हजार रुपया हम प्रति मृतक के परिवार को देंगे । उसके बाद प्रधानमंत्री वहां गए और उन्होंने दो करोड़ रुपया प्रधानमंत्री राहत कोष से दिया । उसमें से 10 हजार रुपया प्रति मृतक पर बार को देने का प्रावधान है यानी 10 हजार रुपया प्रधानमंत्री राहत-कोष से मिलेगा और 15 हजार रुपया इस ट्रस्ट के पैसे से मिलेगा और दोनों को मिलाकर 25 हजार रुपया प्रत्येक मृतक के निकट संबंधी या मृतक परिवार को मिलेगा, जो अब तक साइक्लोन के मामले मे सबसे अधिक दिया जा रहा है।

अंत में, हम माननीय सदन से इतनी दरख्वास्त करेंगे कि हम सभी इस विपत्ति से दुखी हैं और आंध्र प्रदेश या दूसरे जो साइक्लोन से प्रभावित इलाकों के लोग हैं, उनकी तकलीफ में हम लोग उनके साथ हैं, दुखी परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हैं । हम चाहते हैं उनको इस तकलीफ से मुक्ति मिल सके और जल्दी उनका रेस्टोरेशन हो सके, रिहेबिलिटेशन हो सके, इसके लिए हम सभी चिंतित हैं । दलगत भेदभाव से उठकर केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और दूसरी जो संस्थाएं हैं, कुछ स्वयं सेवी संस्थाएं, जिनका मैंने जिक्र किया वहां कार्यरत हैं । अगर समय रहता तो मैं उन स्वयं सेवी संस्थाओं का नाम भी गिना देता, तो सभी की मदद से इस विपत्ति का मुकाबला किया जा रहा है । वहां के लोगों ने जो यह गंभीर नुकसान झेला है, इसके प्रति हम सभी लोगों की हमदर्दी उनके साथ है और हम सभी लोगों का सहयोग उनको मिलेगा। धन्यवाद।

श्री राम नरेश यादव : महोदय, स्वयं सेवी संस्थाओं ने जो अनुदान दिया है ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI) : No. No more speeches. Please pardon me. Yadavji, please pardon me. Please sit down. Now, reply to the debate on price-rise.

SHORT DURATION DISCUSSION

Steep rise in prices of essential Commodities—contd.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI) : The Government attaches the highest priority to containment of inflation and we fully share the concern of hon. Members of the House regarding the rising trend of prices as it hurts the common man, particularly the poorer sections of the community